



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1597]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2019/वैशाख 31, 1941

No. 1597]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2019/VAISAKHA 31, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2019

का.आ.1789(अ).—जबकि, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके बाद उक्त करार कहा गया है), जैसा कि इस अधिसूचना में अनुबंध में दिया गया है, पर मजबूरी, मार्शल आइलैंड गणराज्य में 18 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त करार 6 दिसम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 10 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

कर मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान

हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

भारत गणराज्य की सरकार और मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार, करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन से संबंधित हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत है। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे लम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार, इस बात का ध्यान किए बिना किया जाएगा कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :
 - क) भारत में, केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं ;
 - ख) मार्शल आइलैंड गणराज्य में केन्द्रीय/संघीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किसी तरीके से लगाए गए हैं।
2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :
 - क) पद "भारत" से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसकी सीमा के अंतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;

- ख) पद "मार्शल आइलैंड गणराज्य" से तात्पर्य मार्शल आइलैंड गणराज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किसी भू-राज्य क्षेत्र से है और उसमें मार्शल आइलैंड गणराज्य का आंतरिक जल एवं राज्य क्षेत्रीय समुद्र शामिल है ;
- ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार है जैसा भी संदर्भानुसार अपेक्षित हो ;
- घ) पद "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य -
- (i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ;
 - (ii) मार्शल आइलैंड गणराज्य के मामले में वित्त सचिव अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है;
- ङ) पद "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का समूह और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;
- च) पद "कम्पनी" से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है ;
- छ) पद "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों । शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;
- ज) पद "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति का बहुमत और कम्पनी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;
- झ) पद "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है ;
- ञ) पद "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है -
- (i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज ;
 - (ii) यह स्वीकार किया जाता है कि मार्शल आइलैंड गणराज्य में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ;
 - (iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों ;
- ट) पद "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है । निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;
- ठ) पद "अनुरोध करने वाले पक्ष" से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है ;
- ड) पद "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है ;

- ण) पद "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं ;
- त) पद "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद -9 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय है, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है ।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा । ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष में घटित होता है ।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात का ध्यान किए बिना कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है ।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

- क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना ;
- ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, "आन्सटालटन" और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व शृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना; और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है ।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न किए बिना प्राप्त की जा सकती हो ।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के साथ सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

- क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान ;
- ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है ;
- ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा ;
- घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;
- ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है ;
- च) जहां तक संभव हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है ; और
- छ) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

- क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।
- ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है । अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा । कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :
 - क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो ; अथवा
 - ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी ; अथवा
 - ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।
2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :
 - i) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है; अथवा
 - ii) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक और अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत कानूनी प्रतिनिधि के बीच गोपनीय बातचीत को प्रकट करेगा, जहां ऐसी बातचीत को :
 - (क) कानूनी सलाह मांगने अथवा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो; अथवा
 - (ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी कार्यवाहियों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो ; अथवा
 - iii) प्रशासनिक उपाय करना जो इसके कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर हों, बशर्ते कि इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं पर कोई प्रभाव डालेगा ।
3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है, विवादित है ।
4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने स्वयं के कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने स्वयं के कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा ।
5. यदि सूचना को अनुरोधित पक्ष के कानून के अनुसार अन्यथा उपलब्ध कराया जा सकता है तो अनुरोधित पक्ष केवल इस कारण से सूचना उपलब्ध कराने से मना नहीं करेगा कि अनुरोध में अनुच्छेद 5 के तहत अपेक्षित समस्त सूचना शामिल नहीं है ।

अनुच्छेद 8

विधान का क्रियान्वयन

संविदाकारी पक्ष किसी विधान को अधिनियमित करेंगे जो करार की शर्तों के अनुपालन, और उसे लागू करने के लिए आवश्यक हो । ऐसे विधान को इस करार के लागू होने के छह महीने में अधिनियमित किया जाएगा ।

अनुच्छेद 9

पारस्परिक करार पद्धति

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होती है वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5 और 6 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।
2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के तहत सहमति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 10

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने-अपने कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और तदन्तर तुरंत प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 11

गोपनीयता

1. इस करार के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे सिर्फ संबंधित संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो इस करार में शामिल करें के संबंध में उसके निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उसके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, ऐसी सूचना का प्रयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे ऐसी सूचना को सार्वजनिक न्यायालय संबंधी कार्यवाहियों अथवा न्यायिक-निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की तुरंत लिखित सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति अथवा हस्ती अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार को (जिसमें विदेशी सरकार शामिल हैं) प्रकट नहीं किया जाएगा।
2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सूचना को विदेशी मुद्रा के संबंध में यह करार किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा निकाय को ऐसी सूचना प्रकट करने तथा सूचना का प्रयोग करने की अनुमति भी देता है, जो किसी कानून के अंतर्गत किसी कर, शुल्क या उपकर लागू करने, विदेशी मुद्रा में कार्य करने, स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध प्रवाह को रोकने, अथवा भ्रष्टाचार, आतंकवादी कार्यकलापों अथवा धनशोधन की रोकथाम से संबंधित कार्य कर रहे हैं।
3. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई सूचना को ऐसे दूसरे व्यक्ति को प्रकट किया जा सकता है और ऐसे दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसा भी दोनों पक्षों के कानूनों के तहत स्वीकार्य हो और सूचना सप्लाई करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

अनुच्छेद 12

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. इस करार के समाप्त होने की स्थिति में, ऐसे समापन के होते हुए भी दोनों संविदाकारी पक्ष करार के अंतर्गत प्राप्त की गई किसी भी सूचना के संबंध में अनुच्छेद 11 के उपबंधों के तहत बाध्य होंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

मजुरो, मार्शल आइलैंड गणराज्य में वर्ष 2016 के तीसरे माह के अठारहवें दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से:

मार्शल आइलैंड गणराज्य की
सरकार की ओर से :

सुजान आर. चिनाँय

ब्रेनसन एस. वेस

मार्शल आइलैंड गणराज्य
के लिए भारत के राजदूत

मार्शल आइलैंड गणराज्य के
वित्त मंत्री

[अधिसूचना सं. 40/2019/फा. सं. 503/1/2018-एफटी एंड टीआर-IV]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2019

S.O. 1789(E).—Whereas, the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Marshall Islands for the exchange of Information with respect to taxes (hereinafter referred to as the said Agreement) as set out in the Annexure to this notification, was signed at Majuro, the Republic of the Marshall Islands on the 18th day of March, 2016;

And whereas, the said Agreement entered into force on the 6th December, 2018 being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of the said Agreement, in accordance with Article 10 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS
FOR
THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS**

The Government of the Republic of India and the Government of Republic of the Marshall Islands, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this agreement. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

Information shall be exchanged in accordance with this Agreement without regard to whether the person to whom the information relates is, or whether the information is held by, a resident of a Contracting party. However, a Requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor is in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 - a) In India, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or the Governments of political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied;
 - b) In the Republic of the Marshall Islands, taxes of every kind and description imposed by the Central/Federal Government or the Governments of political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
 - a) The term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

- b) The term “the Republic of the Marshall Islands” means any land territory within the territorial limits of the Republic of the Marshall Islands, and includes the internal waters and territorial sea of the Republic of the Marshall Islands;
 - c) The term "Contracting Party" means India or the Republic of the Marshall Islands as the context requires;
 - d) The term “competent authority” means
 - i) In the case of India, the Finance Minister, Government of India, or its authorized representative;
 - ii) In the case of the Republic of the Marshall Islands, the Secretary of Finance or an authorized representative;
 - e) The term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;
 - f) The term "company" means anybody corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - g) The term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognized stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 - h) The term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
 - i) The term "tax" means any tax to which this Agreement applies;
 - j) The term "recognized stock exchange" means
 - i) In India, the National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange, and any other stock exchange recognized by the Securities and Exchange Board of India;
 - ii) In the Republic of the Marshall Islands, it acknowledges that it does not have a stock exchange; and
 - iii) Any other stock exchange which the competent authorities agree to recognize for the purposes of this Agreement;
 - k) The term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;
 - l) The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 - m) The term "requesting Party" means the Contracting Party submitting a request for information to, or having received information from the requested Party;
 - n) The term "requested Party" means the Contracting Party which is requested to provide information, or which has provided information to the requesting Party;
 - o) The term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested tax information;
 - p) The term "information" means any fact, statement, document or record in whatever form.
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the Contracting Parties agree to a common meaning pursuant to the provision of Article 9 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purpose referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide

- the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
 4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this agreement, has the authority to obtain and provide upon request:
 - a) Information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
 - b) Information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and equivalent information in case of entities that are neither trusts nor foundations.
 5. This Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
 6. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:
 - a) the identity of the person under examination or investigation;
 - b) the period for which information is requested;
 - c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;
 - d) the tax purpose for which the information is sought;
 - e) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
 - f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;
 - g) A statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.
 7. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:
 - a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.
 - b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of the receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other person concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.
2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the

requested party, in which case the competent authority of the requested party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request for information

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
 - a) Where the request is not made in conformity with this Agreement; or
 - b) Where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 - c) Where disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public) of the requested Party.
2. This Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation:
 - i) To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because 'it meets the criteria in that paragraph; or
 - ii) to obtain or provide information, which would reveal confidential communication between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
 - a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
 - b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings; or
 - iii) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under paragraph 4 of Article 5.
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain in similar circumstances under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request from the requested Party under this Agreement.
5. The requested Party shall not decline to provide information solely because the request does not include all the information required under Article 5 if the information can otherwise be provided according to the law of the requested Party.

Article 8

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement. Such legislation shall be enacted with six months of entry into force of this Agreement.

Article 9

Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6 of this Agreement.
2. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Article 10

Entry into Force

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and shall thereupon have effect forthwith.

Article 11

Confidentiality

1. Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction (including a foreign Government) without the express written consent of the competent authority of the requested Party.
2. The information referred to in paragraph 1 may also be disclosed to and used by any officer, authority or body performing any function under any law relating to: the imposition of any tax, duty, or cess; dealings in foreign exchange; the prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances; or the prevention of corruption, terrorist activities, or money laundering.
3. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting Party may be disclosed to such other person and used for such other purposes as allowed under the laws of both Parties and authorized by the competent authority of the Party supplying the information.

Article 12

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Contracting Party.
2. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a written notice of termination to the other Contracting Party through diplomatic channels.
3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the provisions of the Agreement.
4. In the event of termination of the Agreement, notwithstanding such termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 11 with respect to any information obtained under the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Government, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Majuro, the Republic of the Marshall Islands this 18th day of March, 2016 each in the Hindi and English language, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDIA:

Sujan R. Chinoy

Ambassador of India to the

Republic of the Marshall Islands

FOR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS:

Brenson S. Wase

Minister of Finance of the Republic of the Marshall Islands

[Notification No. 40/2019/F.No. 503/1/2018-FT & TR- IV]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.